पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों हेतु विभाग के कार्यक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी

1–स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

परियोजनान्तर्गत क्रमिक उपलब्धि–

- बेसलाईन सर्वे अन्तर्गत चिन्हित कुल परिवारों 2,87,20,844 के सापेक्ष अबतक 2,81,37,821 परिवारों का लाभार्थीवार विवरण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्रतिशत 97.97 है। संख्यात्मक इन्ट्री में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में लक्षित 20,95,669 व्यक्तिगत शौचालय के सापेक्ष 06 मार्च, 2016 2016 तक 5,86,143 शौचालय का निर्माण करा लिया गया है, जो लक्ष्य के सापेक्ष 27.97 प्रतिशत है।
- गंगा के पुनर्जीवन एवं विकास हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा किनारे बसे गॉवों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत स्वच्छता सुविधा से आच्छादन हेतु प्रदेश की 25 जनपदों के 109 विकास खण्डों की 955 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 4,35,184 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराते हुए माह मार्च, 2016 तक शतप्रतिशत आच्छादित किया जाना है, जिसके सापेक्ष अब तक 81,976 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
- प्रदेश में खुले में शौच में मुक्त 153 ग्राम पंचायतें डिक्लेयर की गयी हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है।
- 02 अक्टूबर 2014 के उपरान्त निर्मित 1081510 शौचालयों के सापेक्ष 707458 फोटो अपलोड कर दिये गये हैं जोकि 65.41 प्रतिशत है।

  खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु प्रयास– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु जनपद फिरोजाबाद, कन्नौज, बिजनौर, गोण्डा, मिर्जापुर, वाराणसी आदि के द्वारा सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की गतिविधि सी0एल0टी0एस0 करायी गयी है, जिसके फलस्वरूप इन जनपदों में शौचालय के उपयोग में बढ़ोत्तरी हुई है।
- राज्य स्तर पर सी0एल0टी0एस0 विधा पर दो प्रशिक्षण कराये गये हैं। प्रक्षिक्षित व्यक्तियों द्वारा अन्य जनपदों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

अच्छी प्रगति वाले जनपद– प्रतिशत भौतिक प्रगति के अनुसार 10 अचछी प्रगति वाले जनपद गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, बहराइच, औरैया, मुजफ्फरनगर, शामली, सम्भल, आगरा एवं चन्दौली।

खराब प्रगति वाले जनपद–चित्रकूट, बस्ती, पीलीभीत, हरदोई, बलिया, हापुड, सोनभद्र, गोरखपुर, फैजाबाद एवं मऊ।

बजट प्राविधान वित्तीय (वर्ष 2015–16)–चालू वित्तीय वर्ष हेतु **707.26** करोड़ जनपदों को अवमुक्त किये गये हैं।

वार्षिक कार्य योजना (2016–17)– वित्तीय वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जिसमें अधिक से अधिक पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे 02 अक्टूबर 2019 का लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

स्नानगृह का निर्माणः

ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः शौचालय निर्माण कराये जाने वाले लाभार्थी द्वारा स्नानागृह की मांग की जाती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 5 जनपद–कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, आजमगढ़ एवं सोनभद्र में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्नानागृह निर्माण की योजना संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की महिलाओं/किशोरियों की निजता, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना तथा महिलाओं/किशोरियों को खुले में स्नान की विवशता से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी ही पात्र है।